खिलाफ विचहंटिंग होगी। ऐसा नही होगा, यह हम आपसे आश्वासन चाहते हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मदरसा हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे शिशु मंदिर हो या चाहे विद्यालय हो, यह सब पढ़ाई के मकसद से खोले जाते हैं, और जरूरी हैं। सरकार द्वारा प्राइवेट ऑरग्नाइज़ेशंस खोले जाते हैं। लेंकिन किसी भी स्थल को इनका अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, जहां कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाकर देश के सैक्यूलरिज्म को दूर करने की बात की जाए। चाहे मदरसा हो या विद्यालय हो, हमारे दोनों चीज़े बराबर हैं और सरकार इस संबंध में कटिबद्ध हैं।

Census of Wildlife Animal

*145. SHRIMATI VEENA VERMA: †
SHRI SUSH1L MUMAR SAMBHAJI RAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether census of wild cats, lions, tigers, leopards, panthers and others has been lately held in different wildlife sanctuaries in the country;

(b) if so, when it was last conducted in each sanctuary and what are the comparative figures for each species of animals; and

(c) the yearly rate of growth these figures depict; sanctuary-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Census of major endangered animals are conducted by the States once in four years and in tiger reserves once in two years.

(b) and (c) Last general census of wild animals in major wildlife areas was carried out in 1993. The sanctuary-wise details of wild animal population is not mainted by the Central Government. However, the comparative figures of major wild animals as per 1989 & 1993 census are as under:

		1989	1993	Average Annual Growth Rate (%)
1.	Tiger	4334	3750	(-) 3.36
2.	Elephant	17000—22000	22000—27000	(+) 5.68
3.	Lion	284 (1990)	304 (1995)	(+) 1.40
4.	Leopard	6763	6828	(+) 0.24
5.	Rhinoceros	1591	1496	(-) 1.49
6.	Brow-antlered deer	64	98	(+) 13.28

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Sir, I am on a point of order. My question was whether a census of wild cats...

MR. CHAIRMAN: There is not point of order during Question Hour.

† The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : क्वेश्चन ऑवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर कब से होने लगा हैं...(**व्यवधान**) ...

SHRI SUSHILKUMAR SABHAJIRAO SHINDE: I am on a point of information. *{Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Your turn will come.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: My question was about wild cats...

MR. CHAIRMAN: I will call you when your turn comes.

श्रीमती वीणा वर्मा : माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं कि आपने आंकड़े दिए हैं, इसमें चीते की संख्या के आंकड़ें नहीं दिये हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : दिए हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा : मेरी जानकारी के अनुसार नहीं दिये हैं, चीता वाइल्ड लाइफ से खत्म होता जा रहा हैं। टाइगर भी खत्म हो रहे हैं। यही हमारे देश की सम्पदा है। हमे मनुष्यों पर तो ध्यान ज्यादा देना शुरू कर दिया हैं पर जानवरों पर ध्यान देना कम कर दिया हैं। धीरे-धीरे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा होता कि कि चीतों की संख्या भी देते। अभी हाल में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और मंत्री जी आप बधाई के पात्र हें। आपने वाइल्ड लाइफ की जो संख्या दी हैं, उसके अनुसार संख्या बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश में भी टाइगर की संख्या बड़ी हैं, चीतों की भी संख्या बड़ी हैं, लेकिन जैसे-जैसे वाइल्ड लाइफ को हमने गोटैक्शन देना शुरू किया हैं, टाइगर प्रोजैक्ट्स शुरू किये हैं वैसे-वैस पोचिंग बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गयी हैं और हो रही हैं। टाइगर को बचाने में जिंदा रखने में कम पैसा खर्च होता है और उसके अंग बेचने के लिए बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता हें। यह टाइगर के रख-रखाव में ज्यादा खर्च नहीं आता पर 25 लाख रूपये का एक टाइगर बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में बिकता हैं, नाखून बिकते हैं और उसके वाइटल ऑरगेन्स बिकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हड्डियां भी बेची जा रही हैं। पुरूष लोगा उसके नाखून गले मे पहनते हैं, मांस की धूनी दी जाती हैं, स्किन भी बहुत बड़ी संख्या में बेची जाती हैं और अभी बहुत से मामले पकड़े गये हैं। इसमें खास तौर से तिब्बती लोग इनवसॅल्व हैं। महोदय, पहले तो टाइगर को गोली से मारा जाता था, शिकार किया जाता था पर अब दवा देकर, पैस्टीसाइड देकर या बिजली के खुले तारों से कंरट देकर उसे मारा जाता हैं, शॉक देकर मारा जाता हैं तो अब आप इस पेंचिंग को रोकने के लिए जो ट्रांसपोर्ट ट्रैड का जरिया बन चुका हैं क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और ग्लोबल टाइगर कोरम जो 14 देशों को मिला कर योजना बनी थी, उसमें आपको कहां तक सफलता मिली हैं, वह बताने का कष्ट करें।

श्री कमलनाथ : महोदय, हामारे देश में 88 नैश्नल पार्क हैं और लगभग 440 सैंचुरीज़ हैं जो 142 लाख स्कवेयर किलोमीटर कवर करती हैं यह बात सही है कि जो टाइगर पोचिंग का प्रैशर हैं, यह बढ़ता जा रहा हैं। यह इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे टाइगरों की संख्या हैं, वाइल्ड लाइफ की संख्या हैं, वह बढ़ती जा रही है और जो हमारा हैं वह टाट हैं, जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया हैं उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब आबादी बढ़ती हैं टाइगर की, जब आबादी बढ़ती हैं वाइल्ड लाइफ की तो साथ-साथ उसका एरिया भी बढ़ना चाहिए लेकिन वह नहीं बढ़ता, टाइगर पोचिंग या अन्य पोचिग ज्यादा आसान हो जाता हैं। साथ-साथ साऊथ-ईस्ट-एशियन कंटरीज में टाइगर मेडिशनल फार्मुलेशन, टाइगर को मारना बहुत प्रोफिटेबल होने लगा गया था इसीलिए हमने तीन साल पहले इसको देखते हुए टाइगर स्टैक फोर्स बनाई, टइगर क्रैसिस सेल बनाया। इससे हमने पोचर्स कोपकड़ना शुरू किया इसलिए, नहीं कि यह ज्यादा संख्या में हो रहे हैं बल्कि बात यह है कि अब इन्हें ज्यादा पकड़ा जा रहा हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हैं उसको और मजबूती देने के लिए अन्य चीजें कराई गई हैं। माननीया सदस्या ने पूछा ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में । विश्व में इस बारे मे चिंता प्रकट की गई थीं। टाइगर जो अपने देश में हैं केवल टाइगर क्योंकि टाइगर हैं इसलिए इसकी वेल्यू नहीं हैं बल्कि टाइगर के साथ इसका जो हैबिटाट हैं इसका जो इको सिस्टम होता हैं, कम्पलीट इको सिस्टम होता हैं इस इको सिस्टम को बचाने के लिए टाइगर को बचाने के लिए भी इसकी आवश्यकता हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम हैं और अन्य देश है जो टाइगर स्टेट्स कहलाये जाते हैं उनके साथ एक समझौता किया हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के जो नियम और नीतियां हैं ये देश उसका रैक्टीफिकेशन कर रहे हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं यह कहना चाहती हूं कि टाइगर स्टेट्स में टाइगर को रिजर्व रखने के लिए क्या पालिसी हैं? अभी पिछले 8-9 महीने पहले करीब 8 हजार हेक्टेयर जमीन जो कि वाइटल टाइगर और लैपर्ड हेबिटेट की थी वह स्टेट गवर्नमेंट ने माइनिंग एक्टीटिज़ के लिए दे दी। क्या यह सही हैं? यह पालिस क्या हैं? दूसरे इसको खत्म करने के लिए आप

क्या कर रहे हैं? पहले 6 लाख एकड़ वन जमीन डानेटिड

फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में हैं उसके लिए पैसा दिया जाता था लेकिन अब केन्द्रीय सरकार ने उसको पैसा देना बंद कर दिया हैं तो क्या इसको फिर से चालू करेंगे?

श्री कमल नाथ : यह बात सही नहीं हैं कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेशनल पार्क या प्रोजेक्ट टाइगर एरिया में से भमि माइनिंग के लिए दी गई हैं। अगर ऐसी कोई बात राज्य सरकार में हुई है तो माननीय सदस्या मेरी जानकारी में लायें तब इसमें उचित कार्रवाई की जायेगी।

जहां तक प्रश्न प्राइवेट फोरस्ट को राशि दी जाती थी तो फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट में जो क्लासीफाइड फारेस्ट हो या और किसी प्रकार की हो तो जो भी राशि अन्य राज्यों को दी जाती हैं इस दृष्टिकोण से दी जाती हैं कि उनका एरिया क्या हैं और उसमें काम होता हैं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : सभापति महोदय, एक बात मैंने पूछी थी जंगली बिल्लियों के बारे में। उसके बारे मे यहां इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो अभयारण्य हो रहा हैं,विशेषतः डीपीईपी की ओर से अभरयारण्य हर स्टेट में हो रहा हैं जिसकी वजह से हिरण की संख्या बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो नीयरबाई लेती हैं वहां के किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ होती हैं। मैं सोलापुर के अभयारण्य के बारे में कहना चाहता हूं जिसका नाम नानज नार्थ सोलापुर, महाराष्ट्र हैं। शुरू में यहां पांच हिरण थे आज वहां कम से कम चार हजार हिरण हो गये हैं। इन्होंने वहां की खेती बिल्कुल खराब कर दी हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग डालने का प्रयास आपको करना चाहिए या दूसरा कोई मार्ग निकालना चाहिए। इसका जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए प्रश्न का समय खत्म होने से पहले।

MR CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Construction of Double Decker Coaches

*142. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of RAILWAYS pleased to state:

(a) whether construction of double decker coaches has been discontinued;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the production programme for the same for the next five years and the requirement thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) Prototype of double decker coaches were put on trials a few years back on few trains. Complaints were received regarding dust and noise pollution. Hence no regular production was taken up. Alternate designs of double decker coach are under development.

Working of National Human Rights Commission

*146. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are complaints that the National Human Rights Commission (NHRC) has been venturing into such fields as pollution of environment, lack of housing etc. instead of concentrating on violation of such human rights to look into for which it was primarily set up;

(b) whether Government have made any attempt to assess the achievements and failures of the NHRC and working of the Act; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (c) Government are aware of certain reports in the media, etc., in which views